प्रकाशन का 42 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 43 अंक – 42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पंजीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 15 – 22 अक्तूबर 2018 मूल्य पांच रूपए

ताजपोशीयो के बाद रोष और विद्रोह के स्वर हुए मुखर

जयराम और सत्ती के लिये खड़ी हुई चुनौती

शिमला/शैल। दस माह के इन्तजार के बाद अन्ततः दस और नेताओं को ताजपोशीयों का उपहार नवरात्रों में नसीब हो गया है। इनमें अकेले गणेश दत्त ही हिमफैड की

अध्यक्षता प्राप्त कर पाये हैं और बाकी नौ को उपाध्यक्ष की कुर्सी से ही संतोष करना पड़ा है। इस ताजपोशी से पहले सरकार बनते ही चारों संसदीय क्षेत्रों के संगठन मंत्री और एक मीडिया सलाहकार को ताजपोशियां मिल गयी थी। उसके बाद तीन महिला नेत्रियां तथा कुछ सेवानिवृत अधिकारियों को भी ऐसे ही सम्मान के साथ नवाजा गया था। बल्कि इनमें एक नेत्री तो इतनी भाग्यशाली रही है कि उन्हे कांग्रेस सरकार में भी ताजपोशी प्राप्त थी और अब फिर हासिल हो गयी है। इसी के साथ दो विधायकों नरेन्द्र बरागटा और रमेश धवाला को भी मन्त्री स्तर का सम्मान हासिल हो गया है। इस तरह जयराम सरकार ने भी अब तब तीन दर्जन से अधिक नेताओं को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के रूप में सम्मान से नवाजा है। अभी कई महत्वपूर्ण कुर्सीयां खाली हैं और उम्मीद की जा रही है कि उन्हें भी लोकसभा चुनावों से पूर्व भर दिया जायेगा। क्योंकि पार्टी को फिर से लोकसभा की चारों सीटों पर जीत हासिल करनी है और इसके लिये यदि ताजपोशीयों का आंकड़ा कांग्रेस के आंकड़े से भी बढ़ाना पड़ेगा तो जयराम इसमें भी गुरेज नही करेंगे।

लेकिन क्या इस सबके बावजूद जयराम चारों सीटों पर जीत हालिस कर पायेंगे यह सवाल भी साथ ही खड़ा हो गया है। क्योंकि इन ताजपोशीयों के बाद हमीरपुर के भोरंज और कांगड़ा के इन्दौरा में नाराजगी के स्वर मुखर होकर पार्टी की चौखट लांघकर सड़क तक आ पहुंचे हैं। मनोहर धीमान से तो पद वापिस लेने तक की मांग रख दी गयी है। फिर जब दो विधायकों बरागटा और ध्वाला को ताजपोशी दे दी गई है तो उसी तर्क पर अन्य विधायकों को इससे वंचित कैसे रखा जा सकेगा। जयराम सिद्धान्त रूप से इतनी ताजपोशीयों के पक्षधर नही रहे हैं यह उन्होने ऊना के बंगाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा था। लेकिन अब जब उन्हे यह ताजपोशीयां देनी पड़ी है तो स्वभाविक है कि यह सब उन्हे भारी राजनीतिक दबाव में करना पड़ा है। पार्टी में किस तरह से आन्तरिक समीकरण उलझ चुके हैं इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि जहां-जहां जिला परिषदों और ब्लॉक समीतियों में पासे बदलवा कर सत्ता पर कब्जा करने का प्रयास किया गया वहां पर पूरी तरह सफलता नही मिल पायी है। बंजार में तो जनता ने ही भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नही चल रहा है।

इसके अतिरिक्त आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर भी स्थिति बहुत सहज नही होने वाली है। क्योंकि इस समय पार्टी के शिमला और हमीरपुर के सांसदों के खिलाफ मामले अदालत में चल रहे हैं यदि पार्टी इन लोगों को फिर से उम्मीदवार बनाती है तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इनके मामलों को पार्टी को चुनावों के दौरान पूरी तरह प्रचारित करके मतदाताओं के सामने रखना होगा। ताकि मतदाताओं को इनके खिलाफ चल रहे मामलों की विस्तृत जानकारी मिल सके। इसमें जब ''कैशऑन कैमरा'' जैसा आरोप जनता के सामने जायेगा तो उससे निश्चित रूप से पार्टी की छवि पर नकारात्मक असर पड़ेगा। ऐसे में यह चुनाव सरकार को अपनी ही छवि पर लड़ना पड़ेगा। इस परिदृश्य में शिमला और हमीरपुर के वर्तमान सांसदों के स्थान पर नये उम्मीदवार लाने की मांग उठ सकती है। कांगड़ा के सांसद शान्ता कुमार तो पहले ही कह चुक हैं कि वह अगला चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक नही हैं। इसी के साथ यह सवाल भी उठेगा कि पार्टी किसी महिला को भी चुनाव में उतारती है या नही और उसके लिये कौन सी सीट रखी जाती है। मण्डी से मुख्यमन्त्री की पत्नी के भी उम्मीदवार होने की चर्चाएं काफी समय से चल निकली है और किसी ने इन अटकलों को खारिज भी नही किया है। लेकिन मण्डी से पंडित सुखराम ने भी उनके पौत्र को टिकट दिये जाने की मांग छेड़ दी है ऐसे में इस बार का लोकसभा चुनाव 2014 की तरह आसान रहने वाला नही है।

2014 के चुनाव में भाजपा ने वीरभद्र सिंह के खिलाफ लगे आरोपों को खूब भुनाया था। लेकिन इस बार वही आरोप सरकार के गले की फांस बनने वाले हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अपना ही रिकार्ड बहुत अच्छा नही है। केन्द्र की ऐजैन्सी एनपीसीसी ने ही प्रदेश को आठ करोड़ का चूना लगा दिया है। लेकिन संवद्ध तन्त्र इस पर ऑखे मूदे बैठा है। जबकि कांग्रेस विधायक राम लाल ठाकुर पूरे दस्तावेज़ी साक्ष्यों के साथ एक पत्रकार वार्ता में इस आरोप को उछाल चुके हैं। इसी तरह जहां सरकार 118 की जांच करवा रही है वहीं पर स्वयं इसमें नियमों/कानूनों को अंगूठा दिखा रही है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण घट चुके हैं और उनके दस्तावेजी साक्ष्य भी बाहर आ चुके हैं। सरकार और संगठन इन मुद्दों के प्रति पूरी तरह बेखबर होकर चल रहा है। बल्कि आपस में ही उलझा हुआ है और इस उलझन

का आलम यहां तक पहुच गया है कि पिछले दिनों अमितशाह को जयराम और पवन राणा को इक्कठे बैठाकर लम्बा प्रवचन पिलाना पड़ा है।

यह है नई ताजपोशियां

प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न बोर्डों व निगमों के लिए एक अध्यक्ष व नौ उपाध्यक्षों की नियुक्ति की है। गणेश दत्त को हिमफैड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमीरपुर के विजय अग्निहोत्री को हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष, ऊना के राम कुमार को एचपीएसआईडीसी का उपाध्यक्ष, पूर्व मंत्री प्रवीण शर्मा को हिमुडा का उपाध्यक्ष, किन्नौर के सूरत नेगी को वन निगम का उपाध्यक्ष, शिमला की रूपा शर्मा को सक्षम गुड़िया बोर्ड का उपाध्यक्ष, कांगड़ा के मनोहर धीमान को जीआईसी का उपाध्यक्ष, सोलन के दर्शन सैनी को हिमाचल जल प्रबन्धन बोर्ड का उपाध्यक्ष, सिरमौर के बलदेव तोमर को हि.प्र.

खाद्य एवं आपूर्ति निगम का उपाध्यक्ष तथा कुल्लू के राम सिंह को एचपीएमसी के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है।

जयराम योजनाओं और आंकड़ो पर श्वेत पत्र जारी करें:मुकेश

शिमला/शैल। मुख्यमन्त्री

जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि उन्होने केन्द्र से नौ हजार करोड़ की योजनाएं स्वीकृत करवा ली है। इसी दावे के साथ प्रदेश को सैद्धान्तिक तौर पर मिले 70 राष्ट्रीय उच्च मार्गो के लिये भी केन्द्र से प्रदेश को 65000 करोड़ रूपये स्वीकृत होने को एक बड़ी उपलब्धि कहा जा रहा है। मुख्यमन्त्री के इन दावों की ज़मीनी सच्चाई क्या है इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से इन योजनाओं की तफसील के साथ इस संबन्ध में एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। मुख्यमन्त्री के इन दावों पर इसलिये सवाल उठाये जा रहे हैं क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान मण्डी में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए प्रधानमन्त्री मोदी ने भी वीरभद्र सरकार से 72 हजार करोड़ का हिसाब मांगा था। मोदी ने दावा किया था कि उसकी सरकार ने हिमाचल को 72 हजार करोड़ दिये हैं और सरकार बताये उसने यह पैसा कहां खर्च किया है। लेकिन मोदी के इस दावे पर जयराम के बजट भाशण ने प्रश्नचिन्ह लगा दिया जब बजट मे यह कहा गया कि केन्द्र से प्रदेश को करीब 42 हजार करोड़ मिले हैं। आंकड़ो के इस खेल ने विधानसभा चुनाव में जो प्रभाव दिखाना था वह उस समय हो गया और इसके परिणामस्वरूप यहां पर भाजपा की सरकार बन गयी। क्योंकि उस समय इन आंकड़ों को किसी ने चुनौती नही दी थी। परन्तु अब मुकेश ने आंकड़ो की इस बाजीगरी को समझते हुए मुख्यमन्त्री को इस पर श्वेत पत्र जारी करने की चुनौती दे

शेष पृष्ठ 8 पर.....

राज्यपाल ने किया अन्तर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारम्भ

शिमला/शैल। एक सप्ताह तक चलने वाला अंतराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा महोत्सव पारम्परिक हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ आरंभ हो गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कुल्लू के प्रसिद्ध ढालपुर मैदान में भगवान रघुनाथ जी की रथयात्रा में भाग लेकर दशहरा महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर श्रीमती दर्शना देवी भी उपस्थित थीं।

दशहरा के पावन अवसर पर प्रदेश के लोगों को बधाई देते हुए राज्यपाल ने कहा यह उत्सव बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति बहुत समृद्ध व अद्वितीय है, जिसकी विश्व भर में अलग पहचान है। प्रदेश में वर्ष भर आयोजित होने वाले मेले और त्यौहार यहां के लोगों की समृद्ध परम्पराओं और धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं।

उन्होंने कहा कि आधुनिकता के इस दौर में भी प्रदेश के लोगों ने अपनी समृद्ध संस्कृति और रीति-रिवाजों को संरक्षित रखा है, जिसके लिए वे

बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि इन परम्पराओं और संस्कृति को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की आवश्यकता है।

राज्यपाल ने इस अवसर पर विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया और स्टालों पर जाकर विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया।

कुल्लू दशहरा उत्सव में इस वर्ष क्षेत्र के लगभग 225 देवी-देवता शामिल हुए हैं। इससे पहले, आचार्य देवव्रत का भूंतर हवाई अड्डे पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।

परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह ठाकुर, विधायकगण एवं जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

चामुण्डा मंदिर सौंदर्यीकरण कार्य पर व्यय किए जाएंगे 9 करोड़:किशन कपूर

शिमला/शैल। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर ने कहा कि चामुण्डा माता मन्दिर परिसर के कायाकल्प पर 9 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्य पूरा होने से यहां आने वाले पर्यटकों को तो सुविधा होगी ही, साथ ही स्थानीय युवाओं को रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। किशन कपूर मां चामुण्डा मंदिर में रामनवमीं के अवसर पर आयोजित विशेष पूजा-अर्चना में भाग लेने के उपरांत बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने नवमें नवरात्रे पर मन्दिर में आयोजित यज्ञ में भाग लिया। कपूर ने कहा कि प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा करने हेतू एक नई योजना ''देवभूमि दर्शन'' शुरू की गई है। देवभूमि दर्शन योजना के तहत प्रदेश के 70 वर्ष की आयु वाले

बुजर्गों को 50 फीसदी छूट सरकार देगी जबकि 80 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को प्रदेश सरकार फ्री में देवभूमि के तीर्थ स्थलों के दर्शन करवाएगी। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु वाले यात्रियों के साथ एक परिजन यात्रा कर सकता है, उसे 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि यह यात्रा 8 दिन की होगी।

इस दौरान कपूर ने चामुण्डा मंदिर परिसर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया।

इससे पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दाड़नू में लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान कर दिया तथा शेष समस्याओं के समाधान के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये।

इस अवसर पर नगरोटा बगवां के विधायक अरूण मेहरा, उपायुक्त संदीप कुमार, एसडीएम धर्मेश रामोत्रा, डीएसपी कुशल कुमार, मंदिर अधिकारी सुमन धीमान, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय शर्मा, एसडीओ विनय मेहरा, ओएसडी सुनील शर्मा, पद्दर के उपप्रधान राकेश चौधरी उपस्थित थे।

NOTICE INVITING TENDER
HP.PWD KANGRA

Sealed item rate tenders on form 6 & 8 are invited by the Executive Engineer, Kangra Division, HP: PWD, Kangra on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors/firms enlisted in HPPWD in the appropriate class for the work mentioned below on 12-11-2018 up to 10-45 A.M. and will be opened on the same day at 11-00 A.M. in the presence of intending contractors or their authorized representatives. The tender forms can be obtained from his office on cash payment (non refundable) on any working day from 05/11/2018 to 09/11/2018. The applications for the issue of tender forms will be received latest by 6/11/2018 up to 12.00 Noon. The applications for issue of tender forms accompanied with enlistment letter/or renewal letter and the earnest money in the shape of National Saving Certificates/Saving Account/Time deposit Account in any of the Post Office in Himachal Pradesh duly pledged in favour of Executive Engineer, Kangra Division, HPPWD, Kangra.
The conditional tenders and the tenders received without earnest money will summarily be rejected. The offer of the tender shall be kept open for 120 days.

Work No.1:- Restoration of rain damage on Kangra to Matour road (SH:-Providing and laying Bituminous Macadam concrete pavement in km. 2/105 to 2/210) **Estimated cost:** Rs. 4,91,204/- ***Earnest Money:*** Rs. 9,850/- **Time Limit** One Month **Cost of tender** 350/-.

TERMS & CONDITIONS:-
1. The contractors/firms should be registered as or/dealer under HP Sales Tax Act.1968.
2. The intending contractors/firms shall have to produce the copy of latest enlistment and renewal enlisted in HPPWD.
3. The contractors is required to submit an affidavit for not having more than two works in hand in the shape of affidavit duly attested by the competent authority.
4. If any of the date mentioned above happened to be Gazetted Holiday the same shall be processed on next working day.
5. The contractor should quoted the rates of all the items in the tender both in figures and in words failing which tender is likely to be rejected.
6. The copy of Employees Provident Funds (EPF Number) should be attached with the application.
7. Minimum one similar work done of amount not less than 40% (forty percent) of the estimated cost (without Liquidated Damage or compensation) in last five years).
8. The Earnest Money for the above works should be required at the time of sale of tender forms.
9. All the required document should be submitted with the application otherwise single application may be rejected.
10. The Executive Engineer reserves the right to accept/reject any tender/application or all tenders without assigning any reason.
11. The Contractor should be sole proprietorship of Hot Mix Plant and other required machinery with proof of ownership i.e. RC etc. No affidavit /undertaking to tie up will be entertained.

Adv. No.: 2811/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
मिनाक्षी शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

भारत व तिब्बत की संस्कृति में बहुत समानता:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि भारत में 'अतिथि देवो भव'की संस्कृति रही है। उदारता, प्रेम व सदभावना का संदेश देकर दुनिया की हर संस्कृति का हमने सम्मान किया है और यही भारतीय संस्कृति की विशिष्ट पहचान है।

राज्यपाल भारत में निर्वासित तिब्बती समुदाय के 60 वर्ष पूरा होने पर केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित 'धन्यवाद हिमाचल'कार्यक्रम के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि भारत और तिब्बत की संस्कृति अभिन्न है और सदियों से हमारे व्यापारिक रिश्ते रहे हैं। निर्वासित तिब्बती समुदाय के लोग भारत में प्रेम, एकता व सद्भावना के साथ रह रहे हैं। यही वजह है कि हमने तिब्बती समुदाय को कभी भी अपने से अलग नहीं माना है। यह उनकी महानता है कि 60 वर्षो के अपने निर्वासन के लिए वह भारत के लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं।

आचार्य देवव्रत ने कहा, ''तिब्बती समुदाय की तीसरी पीढ़ी भारत की संस्कृति व भाषा को अपनाकर देश की प्रगति में योगदान दे रही है। इसलिए यह देश आपका उतना ही है, जितना भारत के लोगों का।''

राज्यपाल ने कहा कि भारत की संस्कृति उदार रही है और इस देश ने विदेशी अक्रांताओं तक को अपनाया। तिब्बती लोग, जिनकी मूल संस्कृति बौद्ध धर्म से जुड़ी है और बौद्ध भिक्षुओं ने एकता, बन्धुत्व, प्रेम व भाई-चारे का संदेश दुनिया भर में दिया इसलिए, यह संस्कृति भारतीय संस्कृति से अलग नहीं है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि जो बुनियादी सुविधा भारती मूल के लोगों को मिल रही हैं, वहीं सुविधाएं तिब्बती लोगों को भी प्राप्त हो रही हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि दोनों ही संस्कृतियों का आपसी प्रेम व बंधुत्व भविष्य में भी कायम रहेगा।

राज्यपाल ने इस अवसर पर केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा लगाई की प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया।

इससे पूर्व, बागवानी एवं सिंचाई व जन स्वास्थ्य मंत्री ठाकुर महेन्द्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और हम अपने अतिथि को देव तुल्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार तिब्बती समुदाय को हिमाचली ही मानते हैं। उन्होंने राज्यपाल के मार्गदर्शन में चलाए जा रहे प्राकृतिक कृषि अभियान में तिब्बती समुदाय को भी जुड़ने का आहवान किया।

केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के प्रेजिडेंट लोबसांग सांग्ये ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा कहा कि इन 60 वर्षो में भारत में उन्हें जो प्रेम, संरक्षण व अपनापन मिला है, वह भारतीय संस्कृति की महानता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह भावना आज भी कायम है, जिसके लिए तिब्बती समुदाय आभार व्यक्त करता है। उन्होंने भारत को अपना दूसरा घर बताया तथा कहा कि भारत की उच्च परम्पराओं और समृद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने में तिब्बती समुदाय का भी योगदान है।

इस अवसर पर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का वीडियो संदेश भी प्रसारित किया गया और अपने संदेश में उन्होंने हिमाचली लोगों का आभार व्यक्त किया।

सांसद ने 458 महिलाओं को निशुल्क रसोई गैस कनेक्शन वितरित किए

शिमला/शैल। अनुराग ठाकुर ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत बड़सर विधानसभा परिषद में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा आयोजित बड़सर विधानसभा क्षेत्र की 47 पंचायतों की 458 महिलाओं को निशुल्क गैस कुनैक्शन भी वितरित किये। उन्होने कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार ने यह योजना शुरू कर महिलाओं को धुएं व लकड़ी इक्टठा करने से निजात दिलाई है। इस अवसर पर बड़सर

विधान सभा क्षेत्र के पूर्व विधायक बलदेव शर्मा ने मुख्यातिथि का स्वागत किया। महिला सशक्तिकरण के लिए मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिला हमीरपुर में इस योजना के तहत अब तक 915 महिलाओं को निःशुल्क गैस कुनैक्शन वितरित किए गए है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष एक लाख महिलाओं को हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना के तहत निशुल्क गेस कुनैक्शन वितरित किए जाएगें। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा गैस कुनैक्शन सम्बंधी निर्देश पुस्तिक भी दी जा रही है इसलिए महिलाए सुरक्षा की दृष्टि से गैस संचालन को अच्छी तरह से समझ लें। उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र के गत चार वर्षो के दौरान करोड़ों रूपये की बड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए स्वीकृत करवाये गये हैं जो कि कांग्रेस सरकार 70 वर्षो में नहीं करवा सकी है। उन्होनें कहा कि अगले पांच वर्षो में संसदीय क्षेत्र के विकास पर की दोगुना राशि का प्रावधान किया जाएगा ताकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को एक आदर्श क्षेत्र के रूप में भारत के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जा सके।

इस अवसर पर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक शिव राम राही ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना की उपस्थित लाभार्थियों को विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान बड़सर परिषद सदस्य राजेश सहगल, महासचिव चतर सिंह कौशल, क्षेत्रीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम पंकज शर्मा, एस डी एम विशाल शर्मा, महिला मोर्चा अध्यक्षा कमला देवी, पूर्व मंडलाध्यक्ष प्रकाश चंद, अधिशाषी अभियंता प्रमोद कश्यप के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने की हिमाचल प्रदेश अर्थोपेडिक्स एसोसिएशन के 27वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी में आयोजित हिमाचल प्रदेश अर्थोपेडिक्स एसोसिएशन

के 27वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य के अर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ प्रदेश वासियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने में सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे पर्वतीय क्षेत्रें में जहां दुर्घटनाओं की संभावनाएं अधिक होती हैं वहां आर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ की भूमिका और अधिक बढ़ जाती है।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रसास है कि प्रदेश में अधिक से अधिक ट्रामा सेंटर स्थापित किये जाएं ताकि लोगों को दुर्घटना की स्थिति में तुरन्त चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। उन्होंने प्रदेश सरकार की प्रदेशवासियों के प्रति उनके घरद्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की बचनवद्धता को दोहराते हुए कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में गुणात्मक स्वास्थ सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य संस्थानों को सुदृढ़ कर रही है। प्रदेश में इस क्षेत्र के लिए वर्तमान वितीय वर्ष में 2302 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो विगत वित्तीय वर्ष के 1720 करोड़ रूपये से 582 करोड़ रुपये अधिक है।

स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने इस अवसर पर कहा कि भविष्य में उच्च स्तरीय सेवाएं देने तथा पेश आने वाली समस्याओं में सुधार के लिए ऐसे अधिवेशन नितांत आवश्यक हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि अधिवेशन में हुई चर्चा तथा मंथन से ऑर्थो के क्षेत्र में साकारात्मक व आशातीत परिणाम सामने आयेगें। उन्हांने कहा कि ऑर्थो के क्षेत्र में आई नवीनतम तकनीक से प्रदेशवासी लाभान्वित हो रहे हैं।

कार्यक्रम में हिमाचल चैप्टर के अध्यक्ष डॉ. मुकुन्द लाल ने मुख्य अतिथि तथा अन्यगण मान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा हिमाचल प्रदेश अर्थोपेडिक्स एसोसियशन द्वारा किये जा रहे कार्यो बारे विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री की लोगों से नशे के दानव को समाज से समाप्त करने अपील

शिमला/शैल। शिमला के ऐतिहासिक हनुमान मंदिर जाखू में दशहरा महोत्सव बड़े जोश और उत्साह के साथ

मनाया गया। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति में मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने रावण, कुम्भकरण और मेघनाथ के पुतलों को अग्नि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पर्व अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है। साथ ही यह मां दुर्गा के प्रति श्रद्धा का भी परिचायक है। उन्होंने नशे के दानव को समाज से समाप्त करने के लिए लोगों से मिलजुल कर प्रयास करने की अपील की। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने नौ लाख रुपये की लागत से जाखू मन्दिर परिसर में बनने वाले धार्मिक संग्रहालय का शिलान्यास भी किया। उन्होंने मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर मन्दिर समिति ने मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर, मुख्य सचेतक व विधायक नरेन्द्र बरागटा, मिल्कफेड के अध्यक्ष गणेश दत्त, मुख्य सचिव बी.के. अग्रवाल, नगर निगम शिमला की मेयर कुसुम सदरेट, उप-महापौर राकेश शर्मा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के प्रांत प्रचारक संजीवन, बाल कल्याण परिषद की महासचिव पायल वैद्य, उपायुक्त अमित कश्यप, पुलिस अधीक्षक ओमापति जम्वाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

केन्द्र से उठाएंगे चिनी सुरंग का मामला:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। राज्य सरकार छः माह तक शेष विश्व से कटे रहने वाले पांगी क्षेत्र को हर मौसम सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए चिनी सुरंग के निर्माण का मामला केंद्र सरकार से उठाएगी। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने चंबा जिले के किलाड़ के पांगी में जिला स्तरीय फूलयात्रा उत्सव की अध्यक्षता करते हुए कही।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मन-किलाड़ राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए डीपीआर और सर्वेक्षण कार्य में तेजी लाई जाएगी ताकि इस सड़क का निर्माण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। उन्होंने कहा कि चिनी सुरंग के निर्माण के लिए डीपीआर को समग्र डीपीआर में शामिल किया जाएगा ताकि क्षेत्र हर मौसम में राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा रह सके। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में विकास के नए मार्ग प्रशस्त होंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि विशेष रूप से शीतकालीन मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए क्षेत्र में छोटे सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि लोगों की स्वास्थ्य उपचार सुविधा के लिए क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सक प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों के लाभ के लिए किलाड़ को चार अतिरिक्त एचआरटीसी बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने घोषणा की कि विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए डिग्री कॉलेज किलाड़ में शीघ्र ही तैनात किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने किलाड़ में लड़कियों के लिए एक अलग वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने राजकीय उच्च पाठशाला सुरल को वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में स्तरोन्नत करने और उदान मटोरी में पशु चिकित्सा औषद्यालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने मेला मैदान के विकास के लिए 10 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने उत्सव के आयोजन के लिए मेला समिति को अपनी ऐच्छिक निधि से एक लाख रुपये की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि वह क्षेत्र में संचार कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मामला जियो और एयरटेल के अधिकारियों के साथ उठाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी नेता उनकी दिल्ली यात्राओं के बारे में काफी हो-हल्ला कर रहे हैं। लेकिन अब इन लोगों के होंठों पर ताला लग गया है क्योंकि वर्तमान सरकार राज्य 9000 करोड़ रूपए की केंद्रीय परियोजनाओं को मंजूर करवाने में सफल सफल रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज्य के लोगों के लिए विशेष प्यार और स्नेह है और राज्य के लोगों की विकास आवश्यकताओं के लिए हर संभव

सहायता सुनिश्चित कर रहे हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि घाटी में असमायिक बर्फबारी के कारण चम्बा के होली में सैंकड़ों छात्र फंस गए थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इन सभी छात्रों को केंद्र सरकार की मदद से सुरक्षित रूप से उनके माता-पिता को सौंपना सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चंबा जिला का विकास सुनिश्चित करने के लिए इसका विशेष अनुदान और वित्तीय सहायता के लिए का चयन किया गया है।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने तीन करोड़ रुपये की लागत से किलाड़ में प्राकृतिक पार्क की आधारशिला रखी।

कृषि और जनजातीय विकास मंत्री डॉ. राम लाल मारकण्डा ने कहा कि कार्यालय संभालने के तुरंत बाद वर्तमान राज्य सरकार ने जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए कई फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को अग्रिम वेतन प्रदान किया जाता था, लेकिन पिछली सरकार ने इसे बंद कर दिया था। उन्होंने इस अग्रिम वेतन को फिर से बहाल करने तथा जनजातीय क्षेत्रों के लिए बजट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शून्य लागत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बजट में 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद राम स्वरुप शर्मा ने कहा कि पांगी राज्य के सबसे कठिन क्षेत्रों में से है, जिसे विकास के मामले में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उदारता और मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की प्रतिबद्धता के कारण किलाड़ जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ेगा। उन्होंने सांसद निधि से किलाड़ अस्पताल के लिए एक सप्ताह के भीतर एक एम्बुलेंस की घोषणा की।

भरमौर के विधायक जिया लाल कपूर ने अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि पांगी के लोगों के लिए यह एक गौरवपूर्ण क्षण है कि मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर उनके साथ पांगी घाटी के पारंपरिक फूलयात्रा उत्सव में शामिल हुए हैं। उन्होंने क्षेत्र की विभिन्न विकास मांगों का भी विस्तृत विवरण दिया। उन्होंने क्षेत्र में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और बिजली की समस्या को हल करने के लिए भी मुख्यमंत्री से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पांगी क्षेत्र में पर्यटन की अपार क्षमता है और क्षेत्र में बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो जाने के बाद, यह साहसिक प्रेमियों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभर सकता है।

निवेशकों को आकर्षित करने के लिए धर्मशाला में होगा मेगा निवेशक सम्मेलन

शिमला/शैल। पिछली सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुये जयराम सरकार भी अब हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अगले वर्ष फरवरी माह में धर्मशाला में एक मेगा निवेशक सम्मेलन आयोजित करने पर विचार कर रही है। वीरभद्र सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इस तरह के सम्मेलन इनवैस्टर मीट के नाम पर प्रदेश में व प्रदेश के बाहर किये थे। इस पर बहुत पैसा खर्च किया गया था। अब जयराम सरकार इस मेगा निवेशक सम्मेलन से अन्तर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय परिदृश्य में निवेशकों को हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। इस समय हिमाचल प्रदेश में निवेश के कई लाभ हैं, जैसे कि निवेश मित्र पर्यावरण, व्यापार में आसानी, पर्याप्त बिजली व प्रशिक्षित मानव संसाधन। इस सम्मेलन के माध्यम से कृषि खाद्य प्रसंस्करण, विनिर्माण, ऊर्जा, पर्यटन व संबंधित अधोसंरचना के क्षेत्र में निवेश के लिए हिमाचल प्रदेश को आदर्श राज्य के तौर पर प्रस्तुत करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कृषि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, ऊर्जा, पर्यटन व संबंधित अधोसंरचना, सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी व संबंधित क्षेत्रें पर ध्यान केन्द्रित करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि उद्योग, ऊर्जा व पर्यटन जैसे विभागों के लिए निर्धारित किए लक्ष्य तय समय सीमा के भीतर पूरे कर लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि उद्योग शुरू करने के लिए स्वीकृतियां प्रदान करने की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि जन समस्याओं का निपटारा उनके घर द्वार पर ही करने के लिए राज्य सरकार ने जन मंच कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम लोगों की समस्याओं को दूर करने में सफल साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि जन मंच कार्यक्रमों में लोग अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए भारी संख्या में पहुंच रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जन मंच पहले के कार्यक्रमों की तुलना में काफी अलग है, क्योंकि अब यह कार्यक्रम परिणाम केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जन मंच में प्राप्त हो रही शिकायतों को समयबद्ध तरीके से निपटाने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जन मंच के दौरान लोगों द्वारा उठाई गई शिकायतों के तुरन्त निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने किया डॉ. वाई.एस.परमार विश्वविद्यालय के परीक्षा हॉल का लोकार्पण

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन जिला के डॉ. वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में 2.75 करोड़ रुपये की लागत से नवनिर्मित परीक्षा हॉल का लोकार्पण किया। इस परीक्षा हॉल में 540 विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता के अतिरिक्त स्नातक तथा स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए दो प्रयोगशालाओं सहित अन्य सुविधाएं शामिल हैं।

जय राम ठाकुर ने विश्वविद्यालय में मेजर ध्यान चन्द स्पोर्टस स्टेडियम की आधारशिला रखी, जिसके निर्माण पर 1.21 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। स्टेडियम में एक पैवेलियन भवन के साथ बैठने की व्यवस्था व अन्य अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय द्वारा विकसित नर्सरियों का भी अवलोकन किया तथा इसमें गहरी रूचि दिखाई।

केवल प्रसन्नता ही एकमात्र इत्र है, जिसे आप दुसरे पर छिड़के तो उसकी कुछ बुँदे अवश्य ही आप पर भी पड़ती है।
.....महात्मा गाँधी

सम्पादकीय

शिमला से श्यामला की कवायद क्यों

जयराम सरकार ने शिमला का नाम बदलकर श्यामला करने की मंशा जाहिर की है। इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या रहती हैं इसका इन्तजार किया जा रहा है। यह नाम बदलने का सुझाव विश्वहिन्दु परिषद् की ओर से आया है। ऐसे में यह तय माना जाना चाहिये की कुछ दिनों की बहस के बाद इसे बहुमत की मांग करार देकर यह नाम बदल दिया जायेगा। नाम बदलने से सरकार के ना एक बड़ी उपलब्धि दर्ज हो जायेगी कि उसने ब्रिटिशशासन के एक प्रतीक को बदलकर पुरानी सांस्कृतिक पहचान को पुन: स्थापित करने की दिशा में पहला कारगर कदम उठा लिया है। वैसे तो सरकार की नीयत का पता तो तभी चल गया था जबे शिमला के सौन्दर्यकरण के ऐजैन्डे से यहां स्थित चर्चों की रिपेयर को अचानक नज़र अन्दाज कर दिया गया और उसपर कहीं से भी कोई आवाज नहीं उठी। सरकार के पास अपना पूर्ण बहुमत है इसलिये किसी भी विरोध से कोई फर्क नही पड़ेगा। संघ परिवार का ब्रिटिश और मुगल दासत्ता के प्रतीकों के प्रति किस तरह की धारणा है। इसे सभी जानते हैं। ऐसे में उनके द्वारा बनाये गये भवनों और बसाये गये शहरों के नाम बदलकर अपनी पुरातन संस्कृति की स्थापना करना सबसे आसान काम है। फिर जब योगी आदित्यनाथ इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर सकते है। तो जयराम शिमला को श्यामला क्यों नहीं कर सकते।

आज शिमला को सही में ही श्यामला बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि आज का शिमला कंकरीट के जंगल में बदल चुका है। यह बदलाव कितना भयानक आकार ले चुका है इस पर एनजीटी, प्रदेश उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय तक गंभीर चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं। इसी चिन्ता को स्वर देते हुए यहां नये निर्माणों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। लेकिन शिमला का नाम बदलकर श्यामला करने वाली जयराम सरकार अदालत के इस प्रतिबन्ध को अधिमान देने की बजाये अदालत के फैसले को चुनौती देने की बात कर रही है। अवैध निर्माणों को सख्ती से रोकने की बजाये उन्हे राहत देने के रास्ते निकाले जा रहे है। जब अवैध निर्माणों को रोका नही जायेगा तो फिर नाम बदलकर ही आप शिमला को श्यामला नही बना पायेंगे शिमला में पिछले दिनों पेयजल की कितनी गंभीर समस्या रही है यह पूरे देश के सामने आ चुका है। शहर में पार्किंग की समस्या कितनी गंभीर है इसका आकलन इसी से किया जा सकता है कि प्रदेश उच्च न्यायालय ने नये वाहनों के पंजीकरण के लिये अपनी पार्किंग होने की शर्त लगा दी है। जब तक अपनी पार्किंग उपलब्ध नहीं होगी आप गाड़ी खरीदकर उसका पंजीकरण नही करवा सकते हैं। हर सड़क पर घन्टों ट्रैफिक जाम लग रहे हैं। यह आज के शिमला की व्यवहारिक सच्चाई बन चुकी है। इस समय शहर को इन समस्याओं से निजात दिलाने की आवश्यकता है और इसमें नाम बदलने से कुछ भी हल होने वाला नही है।

बल्कि नाम बदलने की बहस छेड़कर क्या सरकार असली समस्याओं पर से ध्यान हटाने का प्रयास करने जा रही है यह सवाल उठने लग पड़ा है। क्योंकि इस बार बरसात में जो नुकसान हुआ है वह आने वाले समय में एक स्थायी फीचर होने जा रहा है यदि इस समय एनजीटी के आदेशो का आक्षरश: पालन नही किया गया तो निश्चित रूप से ही इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। सरकार वोट की राजनीति के चलते अदालत के फैसलों पर अमल करने का साहस नही जुटा पा रही है। जबकि प्राकृतिक आपदाओं के संकट की चेतावनी हर जिम्मेदार मंच से सामने आ चुकी है। शिमला का रिज और लक्कड़ बाज़ार एरिया 1971-72 में धंसना शुरू हुआ था जो अब स्थायी फीचर बन चुका है। सैंकड़ो करोड़ इस धंसने को रोकने पर खर्च हो चुके हैं। इसलिये आज की आवश्यकता शिमला को संभावित प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिये ठोस और कड़े कदम उठाने की है और यह नाम बदलने से ही होने वाले नही है। फिर आज शिमला को शिमला होने के कारण ही हैरिटेज के नाम पर सौन्दर्यकरण आदि के लिये विश्व संस्थाओं से करोड़ो रूपये मिल रहे हैं क्योंकि हैरिटेज को संजो कर रखा हुआ है। लेकिन कल जब शिमला श्यामला हो जायेगा तो हैरिटेज के नाम पर मिलने वाली सहायता के भी बन्द होने का खतरा हो जायेगा। ऐसे में यह नाम बदलने की कवायद किसी भी तरह से लाभदायक नही रहेगी। इससे केवल एक राजनीतिक बहस चलेगी। हो सकता है कि उससे वैचारिक ध्रुवीकरण तो खड़ा हो जाये लेकिन व्यवहारिक रूप से यह नुकसादेह ही रहेगा।

हिमाचल प्रदेश को स्वस्थ बनाता 'पोषण अभियान'

कुपोषण रोकने के लिए केंद्र सरकार का 'पोषण अभियान' हिमाचल प्रदेश में असरदार साबित होता दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुनझुनू जिला से 8 मार्च 2018 को इस अभियान का शुभारंभ किया गया है। अभियान के पहले चरण में हिमाचल प्रदेश के चंबा, हमीरपुर, सोलन व शिमला जिलों का चयन किया गया। दूसरे चरण में ऊना जिला को इस अभियान के तहत जोड़ा गया। अभियान के तहत बच्चों में ठिगनेपन की समस्या को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। बाल विकास परियोजना, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज और शिक्षा जैसे संबंधित विभागों को मिलजुल कर काम करना है, ताकि नाटेपन की दर को घटाकर कर वर्ष 2022 तक 15 प्रतिशत तक लाया जा सके। मौजूदा समय में ये दर करीब 26 प्रतिशत है।

पोषण अभियान के अन्तर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को शामिल किया गया है। अभियान का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की समस्या को मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करना है, जिसके तहत जन्म के समय नवजात बच्चों के वजन में कमी, रक्त की कमी, भोजन में पोषक तत्वों के असंतुलन को दूर करने के लिए कारगर उपाय अमल में लाना है। इस अभियान के तहत देश के सभी राज्यों में कुपोषण को मिटाने के लिए अभियान छेड़ा गया है। साल 2017-2018 में देश के 315 जिलों को इस अभियान के तहत लाया गया, जबकि 2018-2019 में अन्य 235 जिलों में ये अभियान शुरू किया गया है। बाकी बचे जिलों को साल 2019-2020 में इस अभियान के तहत चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों व अन्य शैक्षणिक संस्थानों में कुपोषण, रक्ताल्पता व अन्य पोषण जन्य विकारों के निदान, रोकथाम व उपचार के बारे में जागरूकता पैदा करते हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. राजीव सैजल ने बताया कि पोषण अभियान के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नौनिहालों की निगरानी स्मार्ट फोन के माध्यम से रखते हैं। उनके खान-पान की निगरानी करने के लिए 5 जिलों के करीब 8000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्ट फोन दिए जा रहे हैं। शेष सात जिलों के 10,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अगले साल अप्रैल महीने में स्मार्ट फोन दिए जाएंगे। रियल टाइम निरीक्षण प्रणाली के माध्यम से मिशन के कार्यों को सुचारू रूप से अंजाम देने के लिए क मन एप्लीकेशन सॉफ्टवेटर तैयार किया गया है। स्मार्ट फोन में यह सॉफ्टवेयर ऑफलाइन भी चल सकता है। आगंनवाड़ी कार्यकर्ता स्मार्ट फोन के जरिए बच्चों का सटीक डाटा एकत्र करते हैं। सॉफ्टवेयर में बच्चे का नाम, माता-पिता का नाम, उसका वजन, उसका कद समेत तमाम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दर्ज की जाती है।

बच्चों का सही डाटा इक्टठा करने के लिए आगंनवाड़ी केंद्रों को इन्फैंटो मीटर, स्टैडीयो मीटर जैसे उपकरण दिए जा रहे हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता वजन का हर महीने रिकॉर्ड दर्ज करते हैं, जबकि लंबाई का रिकॉर्ड हर तीसरे महीने सॉफ्टवेयर में अपडेट किया जाता है।

एकत्र किया गया डाटा रियल टाइम पर डैशबोर्ड के जरिए ब्लॉक, जिला, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के स्टॉफ को उपलब्ध करवाया जाता है। डाटा का आकलन करने के बाद अभियान को सफल बनाने के लिए फैसले लेने में आसानी होगी।

डॉ. सैजल ने कहा कि बच्चों में कुपोषण एक गंभीर समस्या है और इसके निवारण से ही स्वस्थ समाज की परिकल्पना संभव है। हर बच्चा शारीरिक व मानसिक तौर पर स्वस्थ हो, यह परिवार, समाज और देश की आवश्यकता है। उन्होंने पोषण अभियान की शुरूआत अपने घर से करने तथा इसे जन आंदोलन के रूप में निरंतर रखने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति को पोषण से संबंधी जानकारी होनी चाहिए।

पोषण कार्यक्रम के पीछे प्रधानमंत्री की सोच एक स्वस्थ और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करना है। आधो से अधिक बच्चों में खून की कमी होती है। नवजात के लिए मां का दूध एक घण्टे के भीतर मिलना आवश्यक है और बच्चे को कम से कम छ: महीने तक मां का दूध ही दिया जाना चाहिए और इसे दो वर्ष तक जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों में दस्त, न्यूमोनिया व कमजोरी के बहुत मामले सामने आते हैं।

जीवन के पहले 1000 दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इस दौरान तेजी से बच्चे के मस्तिष्क का विकास और शरीर परिपक्व होता है। इस दौरान बच्चे का विकास उसके वयस्क विकास को प्रभावित करता है। इन दिनों पोषण की कमी बच्चे के भावी जीवन पर विपरीत प्रभाव डालती है। तकनीकी का उपयोग, विभिन्न विभागों की योजनाओं का तालमेल तथा जन सहभागिता बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है।

वोट पर नहीं नोट पर जा टिका है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र

पुण्य प्रसून वाजपेयी

देश में फिर बहार लौट रही है। पांच राज्यों के चुनाव के एलान के साथ हर कोई 2019 को ताड़ने में भी से लग गया है। कोई राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ को कांग्रेस के लिये सेमीफाइनल मान रहा है तो कोई बीजेपी के सांगठनिक विस्तार की फाइनल परीक्षा के तौर पर देख रहा है। कहीं मायावती को सबसे बडे सौदेबाजी के सौदागर के तौर पर देखा जा रहा तो कोई ये मान कर चल रहा है कि पहली बार मुस्लिम-दलित चुनावी प्रचार के सौदेबाजी से बाहर हो चुके है। और बटते समाज में हर तबके ने अपने अपने नुमाइन्दों को तय कर लिया है। यानी वोट किसी सौदे से डिगेगा नहीं। तो दूसरी तरफ इन तमाम अक्स तले ये कोई नहीं जानता कि देश का युवा मन क्या सोच रहा है। 18 से 30 बरस की उम्र के लिये कोई सपने देश के पास नहीं है तो फिर इन युवाओं का रास्ता जायेगा किधर। कोई नहीं जानता पूंजी समेटे कॉरपोरेट का रुख अब चुनाव को लेकर होगा क्या। यानी पारपरिक तौर तरीके चूके हैं तो नई इबारत लिखने के लिये नये नये प्रयोग शुरु हो चले है। और चाहे अनचाहे सारे प्रयोग उस इकनॉमिक मॉडल में समा रहे हैं, जहां सिर्फ और सिर्फ पूंजी है। और इस पूंजी तले युवा मन बैचेन है। मुस्लिम के भीतर के उबाल ने उसे खामोश कर दिया है। तो दलित के भीतर गुस्सा भरा हुआ है। किसान - मजदूर छोटी छोटी राहतों के लिये चुनाव को ताक रहा है तो छोटे-मझौले व्यापारी अपनी घाटे की कमाई की कमस खा रहे है कि अबकि बार हालात बदल देंगे। मध्यम तबके में जीने का संघर्ष बढ़ा है। वह हालात से दो दो हाथ करने के लिये बैचेन है। तो मध्यम तबके के बच्चो में जीने की जद्दोजहद रोजगार को लेकर तड़प को बढा रही है। पर इस अंधेरे में उजियारा भरने के लिये सत्ता इतनी पूंजी झोकने के लिये तैयार है कि हर घाव बीजेपी के कारपेट तले छिप जाये। और कांग्रेस हर घाव को उभारने के लिये तैयार है चाहे जख्म और छलनी हो जाये। मलहम किसके पास है ये अबूझ पहेली है। फिर भी चुनाव है तो बहार है। और 2019 के लिये बनाये जा रहे इस बहार में कौन क्या क्या झोकने के लिये तैयार है ये भी गरीब देश पर रईस सत्ता के हंटर की ऐसी चोट है जिसकी मार सहने के लिये हर कोई तैयार है। क्योंकि ये कल्पना के परे है कि एक तरफ दुनिया के सबसे ज्यादा युवा जिस देश में है वह भारत है।

तो दूसरी तरफ देश में लोगों के बदतर सामाजिक हालातों के मद्देनजर सबसे ज्यादा पूंजी चुनाव में ही लुटायी जाती है। अगर 2011 के सेंसस से समझे तो 18 से 35 बरस के युवाओ की तादाद देश में 37 करोड़ 87 लाख 90 हजार 541 थी। जिसमें अब इजाफा ही हुआ है। और 2014 के चुनाव में 1352 करोड़ रुपये चुनाव प्रचार में स्वाहा हुये। जिसमें बीजेपी ने 781 करोड तो कांग्रेस ने 571 करोड़ रुपये प्रचार में फूंके। तो 2019 में चुनाव प्रचार में और कितना इजाफा होगा ये सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि 2004 से 2012 तक कारपोरेट ने राजनीतिक दलो को 460 करोड 83 लाख रुपये की फडिग की थी। लेकिन 2013 में जब बीजेपी ने वाईब्रेंट गुजरात को जन्म देने वाले नरेन्द्र मोदी को पीएम उम्मीदवार बनाया तो 2013 से 2016 के बीच कारपोरेट ने राजनीतिक दलों को 956 करोड 77 लाख रुपये की फडिग की। और इसमें से 75 फीसदी से ज्यादा फडिंग बीजेपी को हुई। बीजेपी को 705 करोड 81 लाख रुपये मिल गये। जबकि कांग्रेस के हिस्से में 198 करोड रुपये ही आये। इतनी रकम भी कांग्रेस को इसलिये मिल गई क्योंकि 2013 में वह सत्ता में थी। यानी मई 2014 के बाद के देश में कारोपरेट ने जितनी भी पालेटिकल फडिंग की उसका रास्ता सत्ता को दिये जाने वाले फडिंग को ही अपनाया। इसके अलावे विदेशी फडिंग की रकम अब भी अबूझ पहेली है क्योंकि अब तो सत्ता ने भी नियम कायदे बना दिये है कि विदेशी राजनीतिक ड को बताना जरुरी नहीं है। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रचार की रकम को समझे तो बीते चार बरस में दो सौ फीसदी तक की बढ़ोतरी 2018 तक हो गई। यानी 2013 में हुये मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव जो पांच बरस बाद अब नवंबर दिसंबर में हो रहे है उसके चुनावी प्रचार और उम्मीदवारों के रुपये लुटाने के तौर तरीकों में अब इतना अंतर आ गया है कि चुनावी पंडित सिर्फ कयास लगा रहे है कि प्रचार में खर्चा 6 हजार करोड़ का होगा या या 60 हजार करोड़। यानी पांच बरस में सिर्फ चुनावी प्रचार का खर्चा ही 900 फीसदी तक बढ़ रहा है। और संयोग से इन तीन राज्यों में बेरोजगारी की रफ्तार भी दस फीसदी पार कर चुकी है। किसानों की कमाई में डेढ़ गुना तो दूर लागत से 20 फीसदी कम हो गई है। सरकारों के जरिये तय न्यूनमत मजदूरी भी दिला पाने की स्थिति में कोई सरकार नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा पर तीनो ही राज्य में खर्च देश के खर्च की तुलना मे 15 फीसदी कम है। और ये तब है जब देश में हेल्थ सर्विस पर जीडीपी का महज 1. 4 फीसदी ही खर्च किया जाता है। दुनिया के आंकडो के सामानातंर भारत की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा की लकीर खिचे तो भारत की स्थिति दुनिया की छठी सबसे बड़ी इक्नामी होने के बावजूद सौ देशो से नीचे है। यानी असमानता की हर लकीर जब जिन्दगी जीने के दौरान पूरा देश भोग रहा है तो फिर चुनाव प्रचार की रकम ये बताने के लिये काफी है कि 30 से 40 दिनो में चुनाव प्रचार के लिये जितना खर्च राज्यों में या फिर 2019 के चुनाव प्रचार में खर्च होने वाला है और पांच राज्यों के प्रचार में शुरु हो चुका है वह रकम 2014 के नरेन्द्र मोदी के उस भाषण पर भारी पड़ जायेगी जिसे वापस लाकर हर व्यक्ति को 15 लाख रुपये देने की बात कह दी गई थी। यानी 2019 में 70 अरब रुपये से ज्यादा सिर्फ प्रचार पर खर्च होने वाले है। और लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिये कितने खरब रुपये राजनीति लुटायेगी इसकी सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है।

और इस परिप्रेक्ष्य में देश जा किस दिशा में रहा है ये सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी के पास फिलहाल देश भर में 6 करोड़ युवा बेरोजगारों की फौज कार्यकत्ता के तौर पर है। और देशभर में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिये करीब 10 करोड़ युवा चुनाव प्रचार के दौरान रोज़गार पा जाते है। कोई बतौर कार्यकत्ता तो कोई नारे लगाने के लिये जुटता है। यानी चुनाव की डुगडगी बजते ही कैसे देश में बहार आ जाती है ये इससे भी समझा जा सकता है कि सबसे ज्यादा काला धन ही इस दौर में बाहर नहीं निकलता है बल्कि हर तबके के भीतर एक उम्मीद जागती है और हर तबके को उस राजनीतिक सौदेबाजी की दिशा में ले ही जाती है जहां सत्ता पैसा बांटती है या फिर सत्ता में आने के लिये हर विपक्ष को अरबों रुपया लुटाना ही पडता है। और अगर इलेक्शन वाच या एडीआर की रिपोर्ट के आंकड़ों को समझे तो चुनावी वक्त में देश में कोई गरीबी रेखा से नीचे नहीं होता बशर्ते उसे वोटर होना चाहिये। क्योंकि देश में तीस करोड़ लोग 28 से 33 रुपये रोज पर जीते हैं, जिन्हें बीपीएल कहा जाता है। और चुनावी प्रचार के 30 से 45 दिनों के दौर में हर वोटर के नाम पर हर दिन औसतन पांच सौ रुपये लुटाये जाते हैं। यानी देश की पूंजी को ही कैसे राजनीति ने हड़प लिया है और देश के अंधियारे को दूर करने के लिये राजनीति ही कैसे सबसे चमकता हुआ बल्ब है ये चाहे अनचाहे राजनीतिक लोकतंत्र ने देश के सामने रख तो दिया ही है ।

केवल पुरुषों को दोष देने से काम नहीं चलेगा

पुरानी यादें हमेशा हसीन और खूबसूरत नही होती। मी टू कैम्पेन के जरिए आज जब देश में कुछ महिलाएं अपनी जिंदगी के पुराने अनुभव साझा कर रही हैं तो यह पल निश्चित ही कुछ पुरुषों के लिए उनकी नीदें उड़ाने वाले साबित हो रहे होंगे और कुछ अपनी सासें थाम कर बैठे होंगे। इतिहास वर्तमान पर कैसे हावी हो जाता है मी टू से बेहतर उदाहरण शायद इसका कोई और नही हो सकता। -डॉ नीलम महेंद्र-

दरअसल इसकी शुरुआत 2006 में तराना बुरके नाम की एक 45 वर्षीय अफ्रीकन- अमेरिकन सामाजिक कार्यकर्ता ने की थी जब एक 13 साल की लड़की ने उन्हें बातचीत के दौरान बताया कि कैसे उसकी मां के एक मित्र ने उसका यौन शोषण किया। तब तराना बुरके यह समझ नही पा रही थी कि वे इस बच्ची से क्या बोलें। लेकिन वो उस पल को नही भुला पाई, जब वे कहना चाह रही थी, **'मी टू', यानी 'मैं भी'**, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई।

शायद इसीलिए उन्होंने इसी नाम से एक आंदोलन की शुरुआत की जिसके लिए वे 2017 में 'टाइम परसन आफ द ईयर' सम्मान से सम्मानित भी की गई।

हालांकि मी टू की शुरुआत 12 साल पहले हुई थी लेकिन इसने सुर्खियाँ बटोरी 2017 में जब 80 से अधिक महिलाओं ने हॉलीवुड प्रोडयूसर हार्वे वाइंस्टीन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया जिसके परिणामस्वरूप 25 मई 2018 को वे गिरफ्तार कर लिए गए।

और अब भारत में मी टू की शुरुआत करने का श्रेय पूर्व अभिनेत्री तनुश्री दत्ता को जाता है जिन्होंने 10 साल पुरानी एक घटना के लिए नाना पाटेकर पर यौन प्रताड़ना के आरोप लगाकर उन्हें कठघड़े में खड़ा कर दिया। इसके बाद तो 'मी टू' के तहत रोज नए नाम सामने आने लगे। पूर्व पत्रकार और वर्तमान केंद्रीय मंत्री एम जे अकबर, अभिनेता आलोक नाथ, रजत कपूर, गायक कैलाश खेर, फिल्म प्रोडयूसर विकास बहल, लेखक चेतन भगत, गुरसिमरन खंभा, फेहरिस्त काफी लम्बी है।

मी टू सभ्य समाज की उस पोल को खोल रहा है जहाँ एक सफल महिला, एक सफल और ताकतवर पुरुष पर आरोप लगा कर अपनी सफलता अथवा असफलता का श्रेय मी टू को दे रही है। यानी अगर वो आज सफल है तो इस 'सफलता' के लिए उसे 'बहुत समझौते' करने पड़े। और अगर वो आज असफल है, तो इसलिए क्योंकि उसने अपने संघर्ष के दिनों में 'किसी प्रकार के समझौते' करने से मना कर दिया था।

यह बात सही है कि हमारा समाज पुरुष प्रधान है और एक महिला को अपने लिए किसी भी क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है।

लेकिन यह संघर्ष इसलिए नही होता कि ईश्वर ने उसे पुरुष के मुकाबले शारीरिक रूप से कमजोर बनाकर उसके साथ नाइंसाफी की है बल्कि इसलिए होता है कि पुरुष स्त्री के बारे में उसके शरीर से ऊपर उठकर कभी सोच ही नही पाता। लेकिन इसका पूरा दोष पुरुषों पर ही मढ़ दिया जाए तो यह पुरुष जाति के साथ भी नाइंसाफी ही होगी क्योंकि काफी हद तक महिला जाति स्वयं इसकी जिम्मेदार है।

इसलिए नही कि हर महिला ऐसा सोचती है। कि वे केवल अपनी प्रतिभा और मेहनत के बल पर सफल नही हो सकती किन्तु इसलिए कि जो महिलाएँ बिना प्रतिभा के सफलता की सीढ़ियाँ आसानी से चढ़ जाती हैं वो इन्हें हताश कर देती है।

इसलिए नही कि एक भौतिक देह जीत जाती है बल्कि इसलिए कि एक बौधिक क्षमता हार जाती है।

इसलिए नही कि शारीरिक आकर्षण जीत जाता है बल्कि इसलिए कि हुनर और कौशल हार जाते हैं।

इसलिए नही कि योग्यता दिखाई नहीं देती बल्कि इसलिए कि देह से दृष्टि हट नही पाती।

आज जब मी टू के जरिए अनेक महिलाएं आगे आकर समाज का चेहरा बेनकाब कर रही हैं तो काफी हद तक कटघड़े में वे खुद भी है। क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि आज इतने सालों बाद सोशल मीडिया पर जो 'सच' कहा जा रहा है उससे किसे क्या हासिल होगा? अगर न्याय की बात करें तो सोशल मीडिया का बयान कोई सुबूत नही होता जो इन्हें न्याय दिला पाए या फिर आरोपी को कानूनी सज़ा। हाँ आरोपी को मीडिया ट्रायल और उससे उपजी मानसिक और सामाजिक प्रतिष्ठा की हानि की पीड़ा जरूर दी जा सकती है। लेकिन क्या ये महिलाएं जो सालों पहले अपने साथ हुए यौन अपराध और बलात्कार पर तब चुप रही इनका यह आचरण उचित है? नही, ये तब भी गलत थी और आज भी गलत है। क्योंकि कल जब उनके साथ किसी ने गलत आचरण किया था उनके पास दो रास्ते थे। उसके खिलाफ आवाज उठाने का या चुप रहने का, तब वो चुप रही।

आज भी उनके पास दो रास्ते थे, चुप रहने का या फिर मी टू की आवाज़ में आवाज़ मिलाने का, और उन्होंने अपनी आवाज उठाई। वो आज भी गलत है। क्योंकि सालों तक एक मुद्दे पर चुप रहने के बजाय अगर वो सही समय पर आवाज उठा लेती तो यह सिर्फ उनकी अपने लिए लड़ाई नहीं होती बल्कि हजारों लड़कियों के उस स्वाभिमान की रक्षा के लिए लड़ाई होती जो उन पुरुषों को दोबारा किसी और लड़की या महिला के साथ दुराचार करने से रोक देता लेकिन इनके चुप रहने ने उन पुरुषों का हौसला बढ़ा दिया। उस समय उनकी आवाज इस समाज में एक मधुर बदलाव ला सकती थी लेकिन आज जब वो आवाज़ उठा रही हैं तो वो केवल शोर बनकर सामने आ रही है। वो कल भी स्वार्थी थी, वो आज भी स्वार्थी है। कल वो अपने भविष्य को संवारने के लिए चुप थी आज शायद अपना वर्तमान संवारने के लिए बोल रही है। यहाँ यह समझना जरूरी है कि यह नही कहा जा रहा ये महिलाएँ गलत बोल रही हैं बल्कि यह कहा जा रहा है कि गलत समय पर पर बोल रही है। अगर सही समय पर ये आवाजें उठ गई होती तो शायद हमारे समाज का चेहरा आज इतना बदसूरत नही दिखाई देता। केवल पुरुषों को दोष देने से काम नही चलेगा। गीता में भी कहा गया है कि अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध है।

नशे के दुष्प्रभावों को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने पर सरकार कर रही विचार:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राज ठाकुर ने सोलन जिला के प्रसिद्ध ठोडो मैदान में नशा निवारण रैली में एलान किया कि उनकी सरकार नशे के बुरे प्रभावों के बारे युवाओं को सचेत करने के लिए इसे स्कूली पाठयक्रम में शामिल करेगी ताकि युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्तता को गैर जमानती अपराध की श्रेणी में लाने के प्रयास किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि नशे की आदत विशेषकर युवाओं में चिन्ताजनक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश इससे अछूता नहीं है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने के लिए पड़ोसी राज्यों से नशे की तस्करी पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं व ड्रग्स तस्करों को पकड़ने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में संयुक्त अभियान शुरू करने के भी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े लोगों को दण्डित करने के लिए कठोर कानून बनाए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बुराई को रोकने के लिए अध्यापकों तथा अभिभावकों की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि अभिभावकों को उनके बच्चों के व्यवहार में आए बदलाव पर भी नजर रखनी होगी। उन्होंने कहा कि कई बार अभिभावक अपने बच्चों में नशे के लक्षणों की अनदेखी करते हैं, जो बाद में गंभीर रूप धारण कर लेता है। उन्होंने कहा कि सिन्थेटिक मादक द्रव्यों का उपयोग और भी खतरनाक है तथा इसके लिए सचेत होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नशे की इस बुराई के विरूद्ध जन अभियान चलाने की आवश्यकता है तभी हमारे देश का भविष्य सुरक्षित रह सकेगा।

उन्होंने आज के दिन को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि देश पुलिस शहिदी दिवस मना रहा है। और 75 साल पूर्व इसी दिन नेता जी सुभाष चन्द्र बोस ने राष्ट्र को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त करवाने के लिए अजाद हिन्द सेना का गठन किया था।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई।

इस मौके पर क्षेत्र के प्रख्यात डॉ. वीरेन्द्र मोहन ने कहा कि विशेषकर 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे नशे की चपेट में सर्वाधिक आते हैं। उन्होंने कहा कि जो सहपाठी व मित्र के दबाव व कई अन्य कारणों से हो सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसे में अध्यापकों तथा अभिभावकों को अपने बच्चों के व्यावहार पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। बच्चों के व्यवहार में आए किसी भी असमान्य बदलाव को गम्भीरता से लेना चाहिए।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने सोलन स्थित माल रोड़ में पुराने उपायुक्त कार्यालय में महिला पुलिस थाने का लोकार्पण किया।

दून के विधायक परमजीत पम्मी, सोलन के विधायक कर्नल धनी राम शाडिल, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ.डेजी ठाकुर, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरषोतम गुलेरिया, पूर्व विधायक विनोद चन्देल, भाजपा नेता एच.एन. कश्यप तथा डॉ. राजेश कश्यप, आईजी पुलिस पुनिता भारद्वाज भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

मुख्यमंत्री ने किया राज्य के लिए चार नई स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारम्भ

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मण्डी जिला के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में 355 करोड़ रुपये की लागत से बने चिकित्सालय, 29 करोड़ रुपये के व्यय से निर्मित हुए उपचारिका शिक्षण महाविद्यालय तथा 3 करोड़ रुपये की धनराशि से निर्मित अपात चिकित्सा केन्द्र का उद्घाटन किया। उन्होंने महाविद्यालय परिसर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राज्य के लिए मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना, हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना, पांगी में टेलीमेडिसिन सेवा आदि चार नई स्वास्थ्य योजनाओं का शुभारम्भ भी किया।

उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक में अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय खोलने तथा अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों के वेतन में प्रतिमाह 10 हजार रुपये तथा अनुबन्ध आधार पर कार्यरत चिकित्सा विशेषज्ञों के वेतन में प्रतिमाह 15 हजार रुपये की बढ़ोत्तरी करने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस महाविद्यालय में चिकित्सालय आरम्भ हो जाने से यहां सभी क्षेत्रों के चिकित्सा विशेषज्ञों के बाह्य व अन्तर रोगी विभाग की सेवाएं उपलब्ध होंगी तथा 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व पूर्व निर्धारित शल्य क्रिया सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी और महाविद्यालय में प्रतिवर्ष 40 उपचारिकाएं प्रवेश प्राप्त करेंगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत न आने वाले रोगियों को जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी तथा मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य देखभाल योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 175 पंजीकृत सरकारी तथा निजी अस्पतालों में निःशुल्क ईलाज की सुविधा के लिए प्रदान की जाने वाली राशि को 30 हजार रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करके लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सार्वभौमिक स्वास्थ्य संरक्षण योजना के अन्तर्गत 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष तक के निःशुल्क ईलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के अतिरिक्त प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र पांगी में टेलीमेडिसिन सेवा के आरम्भ होने से विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा ईलाज व परामर्श की सुविधा भी प्राप्त हो जाएगी। उन्होंने इस अवसर पर मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए नौ विशेष बच्चों को श्रवण यन्त्र (Cochlear Implant) हेतु 5 लाख 50 हजार रुपये प्रति बच्चे की दर से चौक भेंट किए।

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने इससे पूर्व सिविल अस्पताल सुन्दरनगर में 10 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले आवासीय भवन का शिलान्यास, सुन्दरनगर के ललित चौक में 112 लाख रुपये की धनराशि से बनने वाले पैदल चलने योग्य पुल तथा 36.85 लाख रुपये की लागत से निर्मित होने वाले भूतल मार्ग का भी शिलान्यास किया। उन्होंने सिविल अस्पताल में डिजिटल ऐक्स-रे मशीन उपलब्ध करवाने तथा अस्पताल में 100 बिस्तर से बढ़ाकर 150 बिस्तर की सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने बल्ह विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भवन निर्माण हेतु 30 लाख रुपये की धनराशि तथा राजकीय माध्यमिक पाठशाला सरकीधार को राजकीय उच्च विद्यालय में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने रिवालसर उप-तहसील के भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान करके निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की भी अनुशंसा की।

इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री विपिन सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। सरकार का ध्येय संस्थान खोलना ही नहीं अपितु संस्थानों में आधारभूत सुविधाएं व पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध करवाना भी है। उन्होंने कहा कि लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सीय महाविद्यालय नेरचौक में चिकित्सालय की शुरूआत होने से दुर्गम क्षेत्र के लोगों को विशेष रूप से लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को स्वास्थ्य मानकों में अग्रणी राज्य बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सांसद राम स्वरूप शर्मा ने कार्यक्रम में क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। बल्ह विधान सभा क्षेत्र के विधायक इन्द्र सिंह गांधी ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखे।

अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य आर.डी.धीमान ने इस अवसर पर मुख्यातिथि व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया तथा स्वास्थ्य योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक क्षेत्र के विकास के लिए कृतसंकल्प: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार मण्डयाल सभा सोलन को विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सोलन में मण्डयाल भवन के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर सोलन में मण्डयाल सभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभा जिले में मण्डी की संस्कृति, परम्पराओं व रीति-रिवाजों को जीवित रखने व संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सूचना प्रौद्योगिकी युग में विश्व एक वैश्विक गांव के रूप में बदल गया है, परन्तु बावजूद इसके इस तरह के कार्यक्रम विशेष क्षेत्र के लोगों में आपसी भाई-चारे को सुदृढ़ करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

जय राम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने प्रथम दिन से राज्य के सभी क्षेत्रों के कल्याण व विकास के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हालांकि हिमाचली टोपी पहाड़ी संस्कृति की पहचान व गौरव है, परन्तु कुछ निजी स्वार्थों के चलते हिमाचली टोपी को राजनीतिक रंग दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे इस सब के विरूद्ध है और सभी रंगों की टोपी को पहनते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभा की सोलन से धर्मशाला वाया सरकाघाट-मण्डी रात्रि बस सेवा आरम्भ करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन के प्रदेश में स्वीकृत हुए कुल 45217 नए मामले

शिमला/शैल। कांगड़ा जिला में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 9901 नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इस तरह जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों की संख्या पूर्व के 90285 लाभार्थियों से बढ़कर 1 लाख 186 हो गई है। इस पर एक वर्ष में साढ़े 31 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि जिला में सभी पात्र लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के दायरे में लाया जा रहा है। कल्याण विभाग के माध्यम से निर्धन, जरूरतमंद एवं पिछड़े वर्ग के समस्त पात्र लोगों के उत्थान के लिए समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 45217 नए मामले स्वीकृत किए हैं। इस प्रकार प्रदेश में विभिन्न पेंशन योजनाओं में लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 4 लाख 90 हजार हो गई है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 600 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है।

संदीप कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटा कर 70 वर्ष किया है। सरकार समाज के कमजोर व उपेक्षित वर्गों के कल्याण के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह की गई है। अन्य लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 750 रुपये प्रतिमाह की गई है। सरकार यह सुनिश्चित बना रही है कि विकास के लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।

वीरभद्र-धूमल के कार्यकाल में क्या थी प्रदेश की वित्तीय स्थिति सच्चाई सामने आये:विनोद

शिमला/शैल। सरकार पर 50,000 करोड़ रू. के कर्ज पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के ब्यान पर हिप्र. अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि नेता प्रतिपक्ष का यह ब्यान मात्र राजनीतिक है जबकि जयराम ठाकुर सरकार ने अपने कार्यकाल में कभी भी प्रदेश की वित्तीय स्थिति को कमज़ोर नहीं बताया है और प्रदेश के सभी वर्गो को उनके वित्तीय लाभ समय-समय पर दिए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ जन कल्याण के विकास के लिए केन्द्रीय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश को संतोषजनक आर्थिक सहायता केन्द्र दे रहा है जो अपने आप में यह स्पष्ट है कि प्रदेश के कर्ज़े को लेकर प्रतिपक्ष नेता का ब्यान मात्र राजनीतिक है जो अन्य विषयों से ध्यान हटाने का प्रयास है।

महासंघ के प्रदेश संयोजक एवं अध्यक्ष विनोद कुमार ने मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर से मांग करते हुए कहा है कि प्रतिपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री के प्रदेश पर कर्ज़े के ब्यान पर सरकार श्वेत पत्र जारी करे कि पूर्व में धूमल सरकार 2007-12 के सत्ता में आने से पूर्व एवं उनके कार्यकाल और 2012-17 वीरभद्र सरकार के समय प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या रही है ताकि इस महत्वपूर्ण मसले पर प्रदेश की जनता के सामने सच्चाई रखी जाये। महासंघ ने प्रतिपक्ष नेता के उस ब्यान पर भी कटाक्ष किया है जिस पर उन्होंने निगमों और बोर्डों की नियुक्तियों पर सवाल उठाये हैं, पर महासंघ ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल के समय पूर्व में राजनेताओं को सरकारी पदों से कैसे लाभान्वित किया जाये, इसके लिए उस समय की कांग्रेस सरकारों ने विभागों से तोड़कर निगमों और बोर्डों का गठन कर अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के पद सृजित किए ताकि चहेते राजनेताओं को इन पदों से नवाजा जा सके। जबकि निगमों/बोर्डों की वित्तीय हालात हमेशा कमज़ोर रही है जिसके कारण इनमें कार्यरत कर्मचारी वर्ग हमेशा आर्थिक रूप में प्रताड़ित होता रहा है। इसलिए प्रतिपक्ष नेता का इस सम्बन्ध में आया ब्यान पूरी तरह से राजनीतिक है, जिसका जन कल्याण और प्रदेश की कार्य-संस्कृति से कोई सरोकार नहीं है। महासंघ ने कहा है कि यदि विपक्ष में बैठे नेताओं को निगम/बोर्ड फजूलखर्ची का कारण लगते हैं तो वह इन निगमों/बोर्डों को सरकारी विभागों में समायोजित करने की पैरवी करें जिसके लिए कर्मचारी वर्ग उनका समर्थन करेगा अन्यथा विपक्ष में बैठकर इस पर ब्यानबाजी करना मात्र राजनीतिक स्वार्थसिद्धि है।

सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मन्त्रिमण्डल की बैठक में उद्योगों में नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की दर से अधिकतम दो वर्षों के लिए कौशल विकास भत्ता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। ऐसे सभी युवक जिनकी शारीरिक अक्षमता 50 प्रतिशत से अधिक है को इस योजना के अंतर्गत 1500 रुपये प्रतिमाह की दर से यह भत्ता दिया जाएगा और यह भत्ता निजी क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों को मिलेगा जिनका मासिक वेतन 15000 रुपये तक है।

मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग/कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए मेधा प्रोत्साहन योजना को शुरू करने का निर्णय लिया। योजना के तहत सीएलएटी/एनईईटी/आईआईटी-जेईई/एम्स/एफएमसी/एनडीए आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता या वास्तविकता के अनुसार, जो भी कम हो, ऐसे मेधावी छात्रों को प्रदान की जाएगी। बशर्ते विद्यार्थी की सालाना पारिवारिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक न हो। चालू वित्त वर्ष के दौरान इस योजना के तहत पांच करोड़ खर्च किए जाएंगे।

मंत्रिमंडल ने ग्रामीण क्षेत्रों में गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर पहुंच व सुगमतापूर्वक खर्चा वहन करना सुनिश्चित करने तथा निजी क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने व सार्वजनिक स्वास्थ्य लक्ष्यों के साथ सरेखण के लिए तथा स्वास्थ्य प्रणाली को प्रभावी, कुशल, सुरक्षित और किफायती बनाने के लिए राज्य में 'स्वास्थ्य में सहभागिता योजना' आरम्भ करने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत एक करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत का पूंजी उपदान- भवन, मशीनरी और उपकरणों पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निजी क्षेत्र में एलोपैथिक अस्पताल स्थापित करने के लिए किसी भी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट व सोसायटी को निर्धारित क्षेत्र में स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम 75 लाख रुपये की ऋण राशि पर तीन वर्षों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज उपदान प्रदान किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने किन्नौर जिले में 780 मेगावाट जंगी-थोपन- पोवारी जल विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य सतलुज जल विद्युत निगम सीमित को देने का निर्णय लिया। यह भी निर्णय लिया गया कि ऊर्जा विभाग केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों व प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों को आवंटित योजनाओं के निर्माण के लिए एक समय सीमा निर्धारित करेगा।

मंत्रिमंडल ने पुलिस विभाग में 32 वर्ष से अधिक सेवाकाल पूरा करने वाले मानद मुख्य आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी की सेवाओं को मानद सहायक उप-निरीक्षक में पदनामित करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने शिक्षकों की कमी से निपटने के लिए शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से अनुबंध आधार पर विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर शिक्षकों के 230 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने राजकीय बीएड कॉलेज धर्मशाला में विभिन्न श्रेणियों के छः अतिरिक्त पदों को सृजित करने व भरने की मंजूरी प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने मैसर्ज गायत्री जल विद्युत परियोजना (प्राईवेट लिमिटेड) को आवंटित बर्नुआला-बरून्द लघु जल विद्युत परियोजना को दो चरणों में विभाजित करने का फैसला किया। निर्णय के अनुसार दो मेगावाट की चरण-1 बर्नुआला बरून्द की उंचाई सीमा को 1990-1765 मीटर तथा 0.80 मैगावाट क्षमता की बर्नुआला, बरून्द-1 चरण-2 की एलीवेशन रेंज को 1700-1615 मीटर किया गया है। निर्माता कम्पनी को मौजूदा जल विद्युत नीति के तहत प्रीमियम, सुरक्षा शुल्क तथा प्रसंस्करण शुल्क नए सिरे से जमा करना होगा।

मंत्रिमण्डल ने लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडी जिला में मंडी सदर विकास खण्ड तथा सराज विकास खण्ड को पुनर्गठित करके विभिन्न श्रेणियों के दस पदों के सृजन सहित एक नया विकास खण्ड बालीचौकी गठित करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने चम्बा जिले की ग्राम पंचायत बधईगढ़ के कुंगा, ग्राम पंचायत चर्दा के खांडार और ग्राम पंचायत सिंगधार के शाला में इन ग्राम पंचायतों के बच्चों को उनके घर-द्वार पर प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्राथमिक स्कूल खोलने का निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल ने 19 राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं जिनमें कांगड़ा जिले के रा.व.मा.पा. पनाहर-बलाह, कोटलू तथा बहीन, शिमला जिले की रा.व.मा.पा. कांगल, ऊना जिले की रा.व.मा.पा. पलकवाह तथा बसोली, मंडी जिले की रा.व.मा.पा. मोवीसेरी, मलोह, जरोल, मांहूनाग, किलिंग, कमलाह तथा समौर, हमीरपुर जिले के रा.व.मा.पा. बटरान तथा चौड़ू, सिरमौर जिले की रा.व.मा.पा. पुरुवाला, जामनीवाला, बर्मा पापड़ी, बकरास में विज्ञान संकाय की कक्षाएं आरम्भ करने का निर्णय लिया। इसके अलावा मंत्रिमण्डल ने शिमला जिले के रा.व.मा.पा. कांगल, ऊना जिले के रा.व.मा.पा. पंडोगा व पलकवाह, मंडी जिले के रा.व.मा.पा. मोवीसेरी, मोरला, कमलाह, समौर, पांगणा, कांगड़ा जिले के रा.व.मा.पा. बहीन, सिरमौर जिले के रा.व.मा.पा. अजौली व मानपुरा देवरा में वाणिज्य संकाय की कक्षाएं आरम्भ करने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमण्डल ने इन पाठशालाओं में पीजीटी के आवश्यक पदों को सृजित करने व भरने की भी स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने सिरमौर, मंडी तथा ऊना जिले के आठ प्राथमिक पाठशालाओं का स्तरोन्नयन कर माध्यमिक पाठशाला तथा दो माध्यमिक पाठशालाओं का उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नयन करने का निर्णय लिया और साथ ही आवश्यक पदों का सृजन कर इन्हें भरने की भी स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिमण्डल ने मंडी जिला के थट्टा में आवश्यक पदों के सृजन सहित नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की।

मंत्रिमण्डल ने आर्थिकी एवं सांख्यिकी विभाग में परियोजना निदेशक का नया पद सृजित करने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमण्डल की बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य उद्योग विभाग राज्य में उद्यमियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए अगले वर्ष फरवरी माह में ग्लोबल इंवेस्टर मीट आयोजित करेगा। निवेशकों को खाद्य प्रसंस्करण, कृषि, अधोसंरचना विकास, वैलनेस सेंटर, आयुष केन्द्र, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, साहसिक पर्यटन व इको पर्यटन तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए आकर्षित करने पर बल दिया जाएगा।

घरेलू तथा विदेशी उद्यमियों को हिमाचल प्रदेश में अपार संभावनाओं को प्रदर्शित करने के प्रयास किए जाएंगे ताकि वे प्रदेश में निवेश के लिए प्रेरित हो सकें। यह भी निर्णय लिया गया कि यदि आवश्यकता हुई तो निवेशकों की सुविधा के लिए मौजूदा औद्योगिक नीति में संशोधन किया जाएगा।

मंत्रिमण्डल ने भारत रत्न सरदार बल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े पैमाने पर मनाने का निर्णय लिया। राज्य तथा जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें मुख्यमंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डल सहयोगी भाग लेंगे।

भराड़ी पुलिस मैदान में मनाया गया स्मृति दिवस

शिमला/शैल। 21 अक्तूबर 2018 को शिमला के भराड़ी पुलिस मैदान में पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर पिछले एक वर्ष में शहीद हुए भिन्न-भिन्न पुलिस बलों के जवानों के नामों का स्मरण किया गया और उन्हें श्रद्धांजली दी गई। शहीदी दिवस के अवसर पर परेड

का आयोजन भी किया गया। इस स्मृति दिवस में पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश सहित पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शिरकत की। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों आर0आर0 वर्मा, वी0एल0 पण्डित, के0सी0 सड़ियाल, डा0 वी0के धवन एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों व गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

इस अवसर पर होटल पीटरहॉफ में एक सभा का आयोजन भी किया गया जिसमें राज्यपाल महोदय हिमाचल प्रदेश ने शिरकत की। इस समारोह में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों अनुराग गर्ग, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का0एवं व्यवस्था, अशोक तिवारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य गुप्तचर विभाग, ए0पी0 सिंह पुलिस महानिरिक्षक, हिमां ु मिश्रा पुलिस महानिरिक्षक, दलजीति सिंह पुलिस महानिरिक्षक, डा0 खुशहाल शर्मा पुलिस अधीक्षक का0 एवं व्य0,भगत सिंह ठाकुर पुलिस अधीक्षक कल्याण, सेवानिवृत अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्रों, अध्यापकों, सामुदायिक पुलिस योजना एवं नशा निवारण समितियों के सदस्यों व पत्रकारों ने भाग लिया। पुलिस महानिदेशक सीता राम मरडी ने समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल महोदय का हार्दिक अभिन्दन व स्वागत किया।

जहां एक ओर माननीय राज्यपाल महोदय ने पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्बोधित किया वहीं दूसरी ओर उन्हें अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पुलिस की देश की आंतरिक सुरक्षा कायम करने में अहम भूमिका है अतः पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सेवा भाव से कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर प्रश्न काल के दौरान उपस्थित लोगों ने नशा निवारण, सोशल मिडिया पर पुलिस की नमारात्मक छवि के बारे खबरें डालने, पुलिस के शहीदों के प्रति कम श्रद्वा भाव होने व भूतपूर्व सैनिक की तर्ज पर पुलिस के सेवानिवृत कर्मचारियों कल्याण हेतू निगम बनाने सम्बधि प्रश्न पुछे जिनका राज्पाल महोदय ने बड़ी सहजता से उत्तर दिया व मार्ग दर्शन किया। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से इन सवेदनशील मुद्दों पर गहन चिन्तन करने व इन्हें उच्च स्तर पर उठाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहने व विवक के साथ निर्णय लेने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने अपने सम्बोधन में कहा की हमें शहीदों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने देश के सम्मान को कायम रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। साथ ही राज्यपाल महोदय ने शहीदों को भावविनी श्रद्धांजली भी अर्पित की। कार्यक्रम के अन्त में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अनुराग गर्ग ने राज्यपाल महोदय को स्मृति दिवस के विशेष अवसर पर होटल पिटरहाफ शिमला में पधारने के लिए उनका तहदिल से धन्यवाद किया। इस अवसर पर मंच का संचालन सुभ्रा तिवारी हिरा, पुलिस अधीक्षक राज्य नारकोटिक्स ब्यूरो ने किया।

गीता कपूर बनी SJVNL की पहली महिला निदेशक कार्मिक

शिमला/शैल। केंद्र सरकार ने हिमाचल व केंद्र सराकर के संयुक्त उपक्रम सतलुज विद्युत जल निगम के

निदेशक कार्मिक के पद पर गीता कपूर को नियुक्त किया है। इस पद पर नियुक्त होने वाली वह पहली महिला है।

इससे पहले कपूर एसजेवीएन में महाप्रबंधक मानव संसाधन के पद पर तैनात थी। वह नंदलाल शर्मा का स्थान लेंगी जो 1 दिसंबर 2017 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत हो गए थे। एसजेवीएन के वरिष्ठ अपर महाप्रबंधक कारपोरेट संचार शैलेंद्र सिंह ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कपूर का चयन केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सार्वजनिक चयन बोर्ड द्वारा एक साक्षात्कार में किया गया। हिमाचल प्रदेश विवि से एमबीए गीता कपूर की सारी पढ़ाई शिमला में हुई है।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सरकार की सेहत पर भारी पड़ेगा प्रस्तावित राष्ट्रीय राज मार्गो का विकास

शिमला/शैल। केन्द्र सरकार ने हिमाचल को 70 राष्ट्रीय उच्च मार्ग दिये है। इन राजमार्गो के दिये जाने को प्रदेश भाजपा और सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित एवम् प्रसारित किया है। कांग्रेस ने बतौर विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगाया है कि इन राष्ट्रीय उच्च मार्गो की स्वीकृति अभी केवल सैद्धान्तिक स्तर पर ही है और इन्हें अमली शक्ल में अभी वक्त लगेगा। यह सही भी है कि अभी तक इनकी डीपीआर तक तैयार नही हो पायी है। यह सब होने में समय लगेगा लेकिन इतना तय है कि यह राज मार्ग देर सवेर शक्ल लेंगे ही। इस समय चार फोरलेन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसी के साथ अब राज्य सरकार ने टीसीपी का दायरा भी पूरे प्रदेश में बढ़ा दिया है। 150 से ज्यादा नये इलाकों को टीसीपी में शामिल कर दिया है। चार फोरलेन 70 राष्ट्रीय उच्च मार्ग और पूरे प्रदेश को टीसीपी के दायरे ला देना विकास की दृष्टि से एक बड़ा कदम है। यह सारा विकास जब ज़मीन पर उतर कर हकीकत की शक्ल लेगा तब इसका सही आकलन हो पायेगा कि इससे प्रदेश के किसान बागवान और इन पर आश्रित खेती हर मज़दूर को कितना लाभ मिला है। क्योंकि इस विकास को ज़मीन पर उतारने के लिये किसान बागवान की ज़मीन अधिगृहित की जायेगी। क्योंकि विकास के लिये ज़मीन चाहिये और वह केवल किसान-बागवान के ही पास है। किसान/बागवान से क्या उसकी ज़मीन सही मुआवजा देकर ली जा रही है? भू-अधिग्रहण 2013 की सारी शर्तो की अनुपालना हो पा रही है? इसको लेकर सरकार की कथनी और करनी में आये अन्तर को लेकर इस अधिगृहण से प्रभावित लोग पिछले तीन वर्षो से संघर्षरत है। इसके लिये उन्हें प्रदेश स्तर पर संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करना पड़ा है क्योंकि सरकार उन्हें उचित मुआवजा नही दे रही है। इस अधिगृहण से हजारों किसान /बागवान प्रभावित हुए हैं। भाजपा जब विपक्ष में थी तब विधानसभा में भी यह मुआवजे का मुद्दा आया था और तब भाजपा ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए यह मांग की थी उन्हें बाज़ार भाव का चार गुणा मुआवजा दिया जाना चाहिये। लेकिन अब सत्ता में आने पर उसी वायदे को पूरा नही कर पा रही है। संयुक्त संघर्ष समिति ने सरकार को एक माह का समय दिया है यदि इस समय सीमा में इनकी मांगे न मानी गयी तो यह लोग सड़क पर उतर आयेंगे।

भू-अधिग्रहण अधिनियम में चार गुणा मुआवजे का प्रावधान है और इसके आकलन के लिये फैक्टर दो परिभाषित है लेकिन सरकार ने एक अप्रैल 2015 को फैक्टर एक अधिसूचना जारी करके मामले को उलझा दिया। अब फैक्टर एक की अधिसूचना को रद्द करने की मांग पहला मुद्दा बन गया है। 2013 के अधिनियम के शैडयूल दो में भूमिहीन को भूमि,बेघरों को घर, बेरोजगारों को रोजगार अथवा पांच लाख की राशी देने का प्रावधान है। इसी भूमि पर आश्रित खेती हर मजदूरों के भी पुर्नवास और पुन स्थापना का प्रावधान है। अनुसूचितजाति और जनजाति के लोगों के लिये विशेष आर्थिक पैकेज दिये जाने की व्यवस्था है। लेकिन इस दिशा में अभी तक सरकार ऐसे लागों को चिन्हित तक नही कर पायी है जिन्हे यह सब मिलना है। मकानों का मुआवजा वर्तमान दरों की बजाये 2014 की दरों पर दिया जा रहा है। इसमें 12% की दर से ब्याज दिये जाने का भी प्रावधान है और कुछ को यह ब्याज दे भी दिया गया है। पेड़, पौधों व अन्य फसलों का मूल्याकांन 1979 में बने ''हरवंस सिंह फॉर्मूले'' के आधार पर दिया जा रहा है जबकि यह आकलन 2018 के आधार पर किये जाने की मांग है। इस तरह अधिग्रहण से जुड़े इतने मुद्दे हो गये हैं जिनको हल करने के लिये सरकार पर भारी वित्तिय बोझ पड़ेगा। अभी तो मुआवजे की यह मांगे फोरलेन के लिये ली गयी ज़मीन तक ही सीमित है। जब 70 राष्ट्रीय उच्च मार्गो का काम शुरू होगा तब प्रदेश का हर हिस्सा इससे प्रभावित होगा और यह मांग रखेगा।

इस भू-अधिग्रहण के साथ ही अब लोगों की दिक्कत टीसीपी का दायरा पूरे प्रदेश में बढ़ाने से और बढ़ेगी। क्योंकि यह सारे क्षेत्र अब प्लानिंग एरिया में आ जायेंगे। यहां पर होने वाले निर्माणों पर प्लानिंग के नियम/कानून लागू होंगे। एनजीटी के आदेश के बाद अब यहां भी अढ़ाई मंजिल से ज्यादा के निर्माण नही हो पायेंगे। अभी लोगों को इसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी नही है। जब यह जानकारी हो जायेगी तब आम आदमी सरकार के इस फैसले पर कैस प्रतिक्रिया देता है वह रोचक होगा।

ग्रीन एरिया में छत के नाम पर पांचवी मंजिल का निर्माण

शिमला/शैल। एनजीटी ने शिमला के कोर/ग्रीन एरिया में नये निर्माणों पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। इस प्रतिबन्ध के चलते इन क्षेत्रों में केवल पुराने निर्माणों को ही नये सिरे से बनाया जा सकता है। इसके लिये भी नक्शा एनजीटी के फैसले की

अनुपालना में बनाई गयी कमेटीयां ही पास करेंगी। लेकिन क्या प्रशासन एनजीटी के इन आदेशों की अनुपालना करवा पा रहा है यह सवाल शहर के ग्रीन/कोर एरिया में अभी भी चल रहे निर्माणों के कारण उठा है।

शहर का निगम बिहार एरिया ग्रीन एरिया में आता है और इस नाते यहां पर नये निर्माणों पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। पुराने निर्माण भी अढ़ाई मंजिल से ज्यादा के नही बन पायेंगे। यहां पर एक भवन का तीन मंजिलों का निर्माण 1993 में पूरा हो गया था। उसके बाद शायद 1994 में चौथी मंजिल का निर्माण रिटैन्शन के तहत मुआवजा देकर कर लिया गया। लेकिन अब 2018 में एनजीटी के फैसले के बाद पांचवी मंजिल का निर्माण हो रहा है। जब यह निर्माण नगर निगम के संज्ञान में आया तब इस पर नोटिस जारी हुआ लेकिन नोटिस से काम नही रूका। इस पर जब पुन: निगम प्रशासन के संज्ञान में इसे लाया गया तब यह सामने आया कि भवन मालिक से नक्शा मांगा गया है और मालिक का दावा है कि उसका नक्शा पास है।

इसमें यह सवाल उठ रहा है कि जो भवन 1994 में पूरा हो गया है उसमें अब 2018 में एनजीटी के फैसले के बाद छत डालने के नाम पर पांचवीं मंजिल की अनुमति कैसे दी जा सकती है। क्या निगम ऐसी ही अनुमतियां औरों को भी उपलब्ध करवायेंगे? क्योंकि अब तो सभी जगह अढ़ाई मंजिल तक का ही निर्माण होना है। फिर यह छत के नाम पांचवी मंजिल कैसे?

बिना लाइसेंस के ड्राईविंग दे रही हादसों को न्योता

शिमला/शैल। प्रदेश की सड़कों पर सड़क हादसों में मौतें कैसे होती है इस बावत चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इन खुलासों के बाद प्रदेश की जयराम ठाकुर सरकार व उनकी पुलिस को कुछ सोचना जरूर होगा।

सड़क हादसे प्रदेश में रोजाना तीन से चार जानें ले रहे हैं। केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय की ओर से हाल ही में साल 2017 में हुए सड़क हादसों को लेकर हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में 2017 में 1203 लोगों की जानें गई। मायने यह कि हर महीने सौ मौतें। हादसों के पीछे की बड़ी वजहें जो उभर कर सामने आई हैं उनमें ओवर स्पीड, शराब पीकर वाहन चलाना और गलत दिशा में वाहन चलाना शामिल हैं। सबसे ज्यादा हैरानी करने वाला खुलासा इस रिपोर्ट में यह हुआ हैं कि सबसे ज्यादा मौतें उन हादसों में हुई हैं जो साफ मौसम व सीधी सड़क पर हुए हैं। बिना लाइसेंस के वाहन चलाना भी प्रदेश की सड़कों पर मौत की वजह बना हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में शहरों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मौतें हुई हैं और हादसे भी ज्यादा हुए हैं। 2017 में प्रदेश में कुल 3114 हादसे हुए जिनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 2442 हादसे दर्ज हुए हैं और 1072 लोगों की जानें गई हैं। जबकि शहरी क्षेत्रों में 672 हादसों में 131 लोगों की जानें गई। रिपोर्ट के मुताबिक इन हादसों में 1424 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए जबकि 4028 लोग को हलकी चोटें आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश की सड़कों में 907 हादसे भयानक किस्म के थे इनमें से 120 शहरों में व 787 ग्रामीण क्षेत्रों में हुए हैं।

इन हादसों में 1581 ऐसे हादसे चिन्हित हुए हैं जिनमें चालकों के पास वाहन चलाने का लाइसेंस ही नहीं था। 30 के पास लर्नर व बाकी 1553 के पास ही वैध लाइसेंस था। यानि के करीबन पचास फीसद हादसों में चालकों के पास वैध लाइसेंस थे। रिपोर्ट के मताबिक ओवरस्पीड की वजह से 628 सड़क हादसे हुए व इनमें 256 लोगों की मौतें हुई जबकि शराब पीकर वाहन चलाने की वजह से हुए 214 हादसों में 89 लोगों की जानें गई। 1882 सड़क हादसों की वजह गलत दिशा में वाहन चलाना रहा और इस तरह के हादसों में 688 लोगों की मौतें हुई हैं।

इन हादसों में अठारह से कम उम्र के 73 किशोर व 29 किशोरियों की मौत हो गई। जबकि 18 से 25 साल के उम्र के 210 युवकों व 15 युवतियों की मौत हुई हैं। 25 से 35 आयुवर्ग के 279 पुरूषों व 32 महिलाओं, 35 से 45 आयुवर्ग के 194 पुरूष व 29 महिलाओं, 45 से 60 आयुवर्ग के 177 पुरूषों व 43 महिलाओं जबकि 60 साल से ज्यादा उम्र के 95 पुरूषों व 27 महिलाओं की जानें इन सड़क हादसों ने ली हैं। दो पहिया वाहनों के हादसाग्रस्त होने से 336 जानें गई जबकि कार, जीप, वैन और टैक्सियों के हादसाग्रस्त होने से 519 लोगों की मौतें हुई हैं।

मौसम के हिसाब से रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि साफ मौसम में 2733 हादसे हुए व इनमें 1068 लोगों की जानें गई हैं। यानि के हादसों व इनमें होने वाली मौतों का खराब मौसम से कोई लेना देना नहीं हैं। 2017 में बरसात में हुए 161 हादसों में 49, धुंधा की वजह से 212 हादसों में 83 लोगों की जानें गई। रिपोर्ट के मुताबिक सीधी सड़क पर हुए 2016 हादसों में 667 लोगों की मौतें हुई। जबकि घुमावदार व तीखें मोडों पर 763 हादसों में 383 लोगों की जानें गई। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ हैं कि खुली जगह पर हुए सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। 1490 हादसे खुली जगह पर हुए और इनमें 700 लोगों की मौतें हुई हैं जबकि आवासीय क्षेत्र में 626 हादसों में 233 मौतें हुई। बाजारों और वाणिज्यिक इलाकों में हुए 421 हादसों में 97 लोगों की मौतें हुई हैं।

जयराम योजनाओं और आंकड़ों पर

.... पृष्ठ 1 का शेष

डाली है और जयराम इस चुनौती को स्वीकार नही कर पाये हैं। मुख्यमन्त्री इन आंकड़ो के स्पष्टीकरण में केवल यही कर पाये हैं कि यह योजनाएं सिद्धान्त रूप में स्वीकार हुई हैं और इन्हें अमलीशक्ल लेने में वक्त लगेगा। इसी के साथ मुकेश ने जगत प्रकाश नड्डा को लेकर आये ब्यानों और समाचारों पर चुटकी लेते हुए जयराम द्वारा की गयी ताजपोशीयों को दवाब का परिणाम कहा है। बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष सुक्खू ने तो दो कदम और आगे जाकर यहां तक कह दिया कि जयराम तो केवल मुखौटा हैं तथा सरकार तो आरएसएस चला रहा है। मुकेश और सुक्खू के ब्यानों पर पलटवार करते हुए जयराम ने इन्हे यह सुझाव दिया है कि वह अपने घर संभाले क्योंकि वहां पर अभी कई लोगों की नेता प्रतिपक्ष तथा प्रदेश अध्यक्ष होने पर नज़रें लगी हुई हैं। यह सही है कि कांग्रेस में अध्यक्ष को बदले जाने को लेकर इन दिनों अटकलों का बाज़ार बहुत गर्म चल रहा है। कई नाम चर्चा में चल रहे हैं लेकिन इसी के साथ यह भी हकीकत है कि इन दिनों कांग्रेस एक जुट भी होती जा रही है और इस एकजुटता के परिणामस्वरूप आजकल वीरभद्र-सुक्खू के वाक्युद्ध पर भी पूरी तरह विराम लग गया है। इससे यह स्पष्ट संकेत उभर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पूरी तैयारी और रणनीति के साथ उतरने वाली है।